और चौथी श्रेणी के) द्वारा श्रेणीवार देय बिजली और पानी के खर्च की दरों को 1957 से 1967 की अवधि के दौरान कितनी बार बढ़ाया गया तथा हर बार कितनी दरें बढ़ाई गई; और

(ख) इसके क्या कारण थे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जिन सरकारी निवास स्थानों में स्वतंत्र रूप से मीटर नहीं हैं उनसे पानी तथा बिजली का प्रभार, इस बारे में सरकार के द्वारा पिछले वर्ष में किये गये वास्तविक खर्चे के साथ-साथ प्रासंगिक प्रभार के आधार पर मोटी दर (फ्लैट रेट) से वसूल किये जा रहे हैं। दरें निवास स्थानों के टाइप के आधार पर निर्धारित की जाती हैं न कि उनमें रहने वाले कर्मचारियों की श्रेणी के आधार पर। II, III तथा IV श्रेणी के कर्मचारी सामान्यतः टाइप I से लेकर टाईप V तक के निवास स्थानों में रह रहे हैं। सामूहिक मीटरों से युक्त प्रत्येक टाईप के निवास स्थानों के लिए विभिन्न अवधि में पानी के प्रभार की पुनरीक्षित दरों की तारीखों के साथ प्रत्येक टाईप के निवास स्थान के लिए पुनरीक्षित दरों के सात विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या LT - 1192/68] श्रेणी IV के कर्मचारियों को आवंटित टाईप I के निवास स्थानों के संबंध में पानी के प्रभारों में वृद्धि विशेष रूप से इसलिए हुई है क्योंकि इस बारे में सरकार के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को धीरे-धीरे हटाया गया।

जहां तक बिजली के प्रभार का संबंध है, सिवाय लोदी रोड की चमरियों के, जिनसे कि विवरण संख्या 4 में दी गयी मोटी दरों पर प्रभार वसूल किया जाता है, निवास स्थानों में स्वतंत्र रूप से मीटर लगे हुए हैं तथा प्रभारों को कियायेदार के द्वारा सीधे संबंधित स्थानीय निकायों को भुगतान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के बजट का छपना

9727. श्री निहाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश का बजट पहले हिन्दी में छप चुका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसे फिर से अंग्रेजी में छापा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके हिन्दी तथा अंग्रेजी में छापने पर क्रमशः कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश का बजट 14 मार्च, 1968 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 द्वारा संशोधित राज-भाषा अधिनियम की धारा 3 (3) (ii) के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बजट के अंग्रेजी और हिन्दी दोनों संस्करण लोक-सभा सचिवालय को दिये गये थे। इसलिये बजट को अंग्रेजी में दुबारा छापने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) ये बजट-पत्र लखनऊ में राज्य सरकार मुद्रणालय द्वारा, वहां किये जाने वाले सरकारी काम के एक भाग के रूप में छापे गये थे। यह बताना कठिन होगा कि हिन्दी और अंग्रेजी में इन बजट-पत्रों को छापने में अलग-अलग कितनी रकम खर्च हुई।

Tagore Theatre, New Delhi

9729. SHRI J. MOHAMMED IMAM :
SHRI TENNETI VISWANATHAM :
SHRI D. C. SHARMA :

Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a press report in the *Hindustan Times* of the 12th April, 1968 regarding the inordinate delay in the com-

pletion of the Tagore Theatre on the Ridge Road, New Delhi ;

(b) if so, the reasons for the delay in its completion ;

(c) when the theatre is likely to be completed ; and

(d) the total financial allocation made by Government for the construction of the theatre ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes.

(b) to (d). Work on the construction of Rabindra Rangshala was commenced in March, 1961, under the auspices of the Rabindranath Tagore Centenary Committee, a private registered society. An expenditure of Rs. 35.89 lakhs was incurred by the Committee by the 31st March, 1967. Government took over the Rangshala on the 1st April, 1967, and sanctioned an expenditure of about Rs. 11 lakhs to complete the remaining items of work. The entire work was expected to be completed by February, 1968. On account of paucity of funds, however, the work could not be completed as anticipated. The work is now expected to be completed by June this year.

Upgradation of State Bank of India Branch, Bhilai

9730. SHRI J. H. PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there has been a demand from the employees of the State Bank of India, Bhilai to upgrade their Branch to 'B' area ;

(b) if so, the action taken in the matter ;

(c) whether all private sector banks have graded Bhilai as 'B' area for the purpose of determining the service conditions of their employees ; and

(d) if so, the reasons for the delay in the State Bank falling in line ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, the employees of the Bhilai branch of the State Bank have been demanding the inclusion of Bhilai in Area II.

(b) The State Bank has decided to include Bhilai in Area II with effect from the 1st January, 1966.

(c) Yes, Sir.

(d) The matter was under discussion with the All India State Bank of India Staff Federation which had demanded the upgradation of certain other places as well and a final decision could not be taken earlier without considering all the demands together.

Bhatsai Project in Maharashtra

9731. SHRI J. H. PATEL : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5951 on the 1st April, 1968 and state :

(a) when the Municipal Corporation and/or Maharashtra Government first approached the Central Government for assistance to undertake the Bhatsai Project;

(b) the amount of World Bank/I. D. A. assistance necessary to complete the project;

(c) whether any reference has at all been made to the World Bank/I. D. A. so far on this project; and

(d) whether the Maharashtra Government have agreed to provide the necessary capital for the project ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) A preliminary proposal regarding the Bhatsai project was made by the Maharashtra State Government to the Central Government in 1964, but details of Bhatsai and alternate sources have yet to be worked out by the State Government on the basis of the consultant's report which is expected shortly.

(b) The question whether the World Bank/I. D. A. assistance will be necessary, and the quantum of such assistance, will be decided only when details of Bhatsai and alternative projects become known.

(c) The project has been under discussion with the World Bank/I. D. A. for a